(ख) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद से कोयले के मूल्य में कितनी बार वृद्धि की गई है और कुल मिलाकर कितनी वृद्धि की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जनवरी 1974 में गठित अन्तर मंत्रालयिक समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को विचार कर लेने के फलस्वरूप भारत सरकार ने 1-4-1974 से कोयले के विभिन्न ग्रेडों के खान-मुहाना मूल्यों में वृद्धि करना स्वीकार कर लिया है । औसत वृद्धि लगभग 10 रुपये प्रति टन बैठती है ।

(ख) कोककर कोयला खानों के 1-5-1972 से राष्ट्रीयकरण से भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा उत्पादित कोककर कोयले के मूल्यों में तीन बार वृद्धि की गई है और कोयला खान प्राधिकरण लि० द्वारा उत्पादित कोयले के मूल्यों में राष्ट्रीयकरण अर्थात् 1-5-1973 से एक बार वृद्धि की गई है । मूल्य वृद्धि कोयले के ग्रेड के अनुसार भिन्न-भिन्न मात्रा में है ।

बोनस पुनर्विलोकन समिति की सिफारिशें

*73. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोनस पुनर्विलोकन समिति (बोनस रिव्यू कमेटी) की मुख्य सिफारिशें क्या है;

(ख) उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) रेल, डाक तथा तार विभाग, रक्षा उत्पादन, सड़क व विमान परिवहन और पोतवहन तथा अन्य सरकारी उपक्रमों में कब से समान दर से बोनस दिया जायेगा और वह दर क्या होगी ?

1157 L S—2

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) समिति की रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की गई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Workers Laid off in 1972-73 due to Closure of Factories following Power Crisis

*74. DR. RANEN SEN:
SHRI CHIRANJIB JHA:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the number of workers laid off during 1972-73 due to the closure of factories following power crisis; and

(b) whether Government are considering any proposal to amend the Industrial Disputes Act for increasing the lay-off compensation?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI RAGHUNATHA REDDY): (a) A statement which summarises the available information about the number of workers laid off during 1972-73 due to the closure of factories arising from power shortages is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-8038/74].

(b) The question of amending the lay-off provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, is under Government's consideration.

दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा

*75. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) क्या उपरोक्त प्रतिनिधि मंडल से उनके साथ कोई बातचीत की थी और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या प्रतिनिधिमंडल ने अपनी सरकार की मान्यता का प्रश्न उठाया था और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां । पिछले महीने काठमाड़ू में अफ्रीकी-एशियाई शांति एवं एकता संगठन के वार्षिक महासम्मेलन में भाग लेने के पश्चात् यह प्रतिनिधिमंडल भारत में रुका था।

(ख) इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य जब विदेश मंत्री से मिलने आये थे उस समय बातचीत में वियतनाम की स्थिति पर विचार किया गया ।

(ग) जी हां , दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता प्रदान करने का प्रश्न अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

Commissioning of Vijayanagar Steel Plant in Karnataka

*76. SHRI K. MALLANNA:
SHRI K. LAKKAPPA:

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) the estimated cost of Vijayanagar Steel Plant in Karnataka;

(b) the estimated production of steel from the Plant and by when it is to be commissioned;

(c) the amount of money spent, whether the Plant was allowed to import key items and the progress so far made; and

(d) the allotment of funds made for the Plant in the Fifth Five Year Plan?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI K. D. MALAVIYA) (a) The estimated total capital outlay on the Vijayanagar Steel Plant (on the basis of 1972 prices) is about Rs. 854 crores.

(b) The plant is proposed to be designed for a capacity of about 3.35 million tonnes of liquid steel, to be processed into 2.310 million tonnes of hot rolled strips and 0.655 million tonnes of billets. The plant is likely to be commissioned during the Sixth Five Year Plan period.

(c) The expenditure on the project up to the end of 1973-74 was about Rs. 1.44 crores.

The Steel Authority of India Ltd. are taking action for the preparation of the Detailed Project Report. Meanwhile, land acquisition work and studies for the development of infrastructure facilities are in progress. No items of plant and equipment have been ordered as this question will come up for consideration only after the Detailed Project Report is received and scrutinised and a view is taken on the phasing of implementation of the works.

(d) In the draft Fifth Five Year Plan, which is yet to be finalised a provision of Rs. 125 chores has been proposed for this project.

National Wage Policy

*77. SHRI BANAMALI BABU:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government propose to evolve a national minimum wage policy for the entire working class covering the industrial as well as agricultural workers; and

(b) if so, the salient features thereof?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI RAGHUNATHA REDDY): (a) and (b): There is yet no proposal for evolving a national minimum wage for the entire working class.